डॉ। इकबाल सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त निदेशक, युवा कल्याण बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य (के. कन्नन, न्यायमूर्ति.)

**के कन्नन न्यायमूर्ति के समक्ष**

**डॉ। इकबाल सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त निदेशक, युवा कल्याण)-याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य-प्रतिवादी**

**सीडब्ल्यूपी नं. 2009 का 8966**

**09 मई 2012**

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - विश्वविद्यालय कर्मचारी भविष्य निधि विनियम - तत्संबंधी। 6 - भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि याचिकाकर्ता को इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया कि उसने अपनी सेवा के दौरान युवा उत्सव के आयोजन के लिए ली गई अग्रिम राशि का हिसाब नहीं दिया था - सेवानिवृत्ति की तारीख तक ऐसी देनदारी निर्धारित नहीं की गई है क्या भविष्य निधि के संचय से देय और देय राशि हो सकती है कथित दायित्व निर्धारित करने के लिए रोक दिया गया - याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी राशि के लिए जिसका पता नहीं लगाया गया है और बिना जांच के टर्मिनल लाभों का भुगतान न करना अस्थिर है - रिट याचिका में उस कर्मचारी को रोकने की अनुमति दी गई है जिसने अपने दायित्व से इनकार कर दिया है, सक्रिय होने के अभाव में उस पर ऐसी देनदारी नहीं डाली जा सकती उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दायित्व निर्धारित करने का दृष्टिकोण।

माना गया, कि नियोक्ता, हर समय अपने वित्त का संचालन करेगा इस तरह से कि किसी भी कर्मचारी को दी जाने वाली अग्रिम राशि जिसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार है, ऐसे लेखांकन की मांग को सुरक्षित किया जाना चाहिए और सेवा के दौरान ही दायित्व को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। जब दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता है तो दो विकल्प होते हैं - (i) कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं होने देना, जांच गठित करना और दायित्व को अंतिम रूप देना; (ii) ऐसे किसी विशेष प्रावधान को लागू करें जो नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद जांच के गठन की अनुमति देता हो। विनियम 6 पर निर्भरता केवल उन स्थितियों में संभव होनी चाहिए जहां दायित्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो। यदि उचित न्यायनिर्णयन और दायित्व के अंतिम निर्धारण के बिना दायित्व से इनकार कर दिया जाता है। नियोक्ता कर्मचारी को सेवानिवृत्ति बकाया का दावा करने से नहीं रोकेगा।

पैरा (4)

आगे कहा गया, कि जब सेवानिवृत्ति लाभों का वितरण करने के लिए नियोक्ता के कर्तव्य की बात आती है तो मुद्दा कितना गंभीर है, इस बारे में कई न्यायिक दृष्टिकोण हैं। ऐसे निर्णय भी हैं जो मानते हैं कि भविष्य निधि के लिए देय राशि का कोई भी हिस्सा कुर्की का विषय नहीं हो सकता है। एक कर्मचारी जिसने अपने दायित्व से इनकार किया है, उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दायित्व निर्धारित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के अभाव में ऐसे दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है। इससे भी अधिक, इस मामले में, जिस देनदारी को तय करने की मांग की गई थी, वह सेवानिवृत्ति पर या उससे ठीक पहले प्राप्त अग्रिम के लिए नहीं थी, बल्कि सेवा के दौरान 20 वर्षों की अवधि में दिए गए अग्रिम के लिए थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. शीतल प्रसाद नागेन्द्र एवं अन्य; एआईआर 2001 एससी 2443 पर भरोसा किया गया।

पैरा (7)

आगे कहा गया, नियमों द्वारा स्वीकार्य किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हुए बिना भविष्य निधि से कटौती को बचाव योग्य नहीं माना गया। देनदारी के विरुद्ध कथित समायोजन पर भविष्य निधि की बकाया राशि जारी न करना, जो निर्धारित नहीं है, को भी अस्थिर माना गया है। भविष्य निधि बकाया का भुगतान 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया।

पैरा (8)

प्रतिवादियों की ओर से दीपक सिब्बल, अधिवक्ता

के. कन्नन, न्यायमूर्ति

(1) रिट याचिका एक सेवानिवृत्त निदेशक, युवा कल्याण के उदाहरण पर है, जो दावा करते हैं कि भविष्य निधि और अन्य सभी सेवानिवृत्ति बकाया को एक विशेष आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उन्होंने जो अग्रिम लिया था उसका हिसाब नहीं दिया था। अपनी सेवा के दौरान कई युवा महोत्सवों का आयोजन। उनकी सेवानिवृत्ति तक देनदारी का निर्धारण नहीं किया गया था और उन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति दिए जाने के बाद, पूरे टर्मिनल लाभों को इस आधार पर रोक दिया गया है कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के प्रति याचिकाकर्ता की देनदारी उसे देय राशि से कहीं अधिक है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उस राशि के लिए जिसका पता नहीं लगाया गया है और दायित्व तय करने के लिए जांच किए बिना, टर्मिनल लाभों का भुगतान न करना स्पष्ट रूप से अस्थिर है। इसलिए, विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या भविष्य निधि के संचय के लिए देय और देय राशि को उसके द्वारा प्राप्त अग्रिमों के लिए उसके द्वारा कथित दायित्व के खिलाफ याचिकाकर्ता की पात्रता को समाप्त करके अस्वीकार किया जा सकता है और जिसका विधिवत हिसाब नहीं किया गया था। . कुछ और तथ्य आने जरूरी होंगे इस रिट याचिका के माध्यम से सामने आई समस्या के समाधान के लिए

डॉ। इकबाल सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त निदेशक, युवा कल्याण बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य (के. कन्नन, न्यायमूर्ति.)

(2) याचिकाकर्ता 31.03.1978 को युवा कल्याण विभाग, चंडीगढ़ के निदेशक और प्रमुख के रूप में सेवाओं में शामिल हुए थे और 30.04.2005 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 1978 से 2005 तक युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से समय-समय पर अग्रिम राशि ली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को अनुदान और सब्सिडी दी गई थी युवा उत्सव आदि आयोजित करने के लिए कॉलेजों को आगे संवितरण। याचिकाकर्ता को दिए गए कई अग्रिमों में से, लेखापरीक्षा को 25 सब्सिडी के साथ 33 अग्रिमों पर आपत्ति थी जो असमायोजित और बेहिसाब रहीं। याचिकाकर्ता को खातों का मिलान करने और उसे दिए गए अग्रिमों का विधिवत हिसाब-किताब करके उसे अंतिम रूप देने के लिए कई नोटिस दिए गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क होगा कि उन्होंने सभी स्पष्टीकरण दे दिए थे और विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्वयं लगभग रुपये के व्यय/उपयोग से संबंधित दो आपत्तियों के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी दे दी थी। 08.04.2000 को 1,40,000/-। 31 अन्य अग्रिमों के संबंध में, याचिकाकर्ता दावा करेगा कि डिस्पैच रजिस्टरों की प्रतियों सहित आधिकारिक रिकॉर्ड से पर्याप्त सबूतों की प्रतियां समय-समय पर धन के उपयोग, खातों के समायोजन और व्यय रिपोर्ट के पूरे विवरण के साथ दी गई थीं। याचिकाकर्ता कई संचारों पर भरोसा करेगा जो उसके लेखा विभाग के साथ थे और पूर्ण विवरण जो उसने विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया था और जब 20.01.2004 को एक विशेष घटना पर, रजिस्ट्रार के कार्यालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और सबूतों को खारिज कर दिया था। पत्र दिनांक 20.01.2004 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.02.2004 के माध्यम से खातों के समायोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज/जानकारी देते हुए उठाए गए संदेहों के लिए स्पष्टीकरण देने की मांग की थी।

(3) सच्चाई यह है कि उत्तरदाता याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अग्रिमों के लिए उचित लेखांकन की मांग कर रहे थे और अग्रिमों की प्राप्ति से इनकार नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य निधि राशि का भुगतान न करने का औचित्य विश्वविद्यालय कर्मचारी विनियमन के भविष्य निधि विनियमन 6 पर निर्भरता है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"विश्वविद्यालय के प्रति देयता के तहत देय राशि के संबंध में ग्राहक से, ब्याज सहित, विश्वविद्यालय के योगदान की राशि से अधिक की राशि की फंड से कटौती की जा सकती है।"

विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या कटौती उस राशि के संबंध में की जा सकती है जो अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। यह मानते हुए कि यह राशि किसी कर्मचारी द्वारा निकाली गई थी और उसकी सेवा के दौरान उसका विधिवत हिसाब नहीं किया गया था, तो क्या कर्मचारी के लिए उसे देय भुगतान से इनकार करना और कर्मचारी पर डाली गई देनदारी को अंतिम मान लेना संभव होगा, हालांकि कर्मचारी कटौती पर आपत्ति जताता है? प्रश्न का उत्तर सीधा और सरल है. भविष्य निधि की पात्रता का आकलन उसकी सेवा के दौरान संगठन में कर्मचारी के स्वयं के योगदान के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा वैधानिक आदेशों के माध्यम से किए गए योगदान से किया जाता है। राशि एक वैधानिक अधिकार है और यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर

कोई दायित्व काटा जाना है, तो इसे केवल उस राशि के संदर्भ में निकाला जा सकता है जो एक उचित प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

(4) इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता पर डाली गई देनदारी उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर प्राप्त किसी भी राशि के लिए नहीं है, बल्कि ये अग्रिम 20 वर्षों से अधिक की सेवा अवधि के दौरान होने का तात्पर्य है। नियोक्ता, हर समय, अपने वित्त का संचालन इस तरह से करेगा कि किसी कर्मचारी को दी जाने वाली अग्रिम राशि के लिए, जिसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार है और खाते के लिए बाध्य है, ऐसे लेखांकन की मांग को सुरक्षित किया जाना चाहिए और दायित्व को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सेवा ही. जब दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता है तो दो विकल्प खुले होते हैं: (i) कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं होने देना, जांच गठित करना और नियोक्ता के प्रति कर्मचारी के दायित्व को अंतिम रूप देना; (ii) ऐसे किसी विशेष प्रावधान को लागू करें जो नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद जांच के गठन की अनुमति देता हो। ऐसी स्थिति में जहां कटौती की जाने वाली राशि पर कर्मचारी द्वारा विवाद किया जाता है, नियोक्ता के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वह अंतिम रूप से मूल्यांकन की जाने वाली राशि मान ले। इससे नियोक्ता की मनमानी कार्यप्रणाली से कर्मचारी को उसके जीवन के शाम के वर्षों में मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। विनियम 6 पर निर्भरता केवल उन स्थितियों में संभव होनी चाहिए जहां दायित्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो। यदि उचित न्यायनिर्णयन और ऐसे दायित्व के अंतिम निर्धारण के बिना दायित्व से इनकार कर दिया जाता है, तो नियोक्ता कर्मचारी को संपूर्ण सेवानिवृत्ति शुल्क का दावा करने से नहीं हराएगा।

(5) याचिकाकर्ता की मांग को अस्वीकार एक याचिका पर किया गया है प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 08.09.2008 के माध्यम से बताया कि राशि ऑडिट आवश्यकताओं के अनुपालन तक भुगतान नहीं किया जाएगा। मुझे यह उत्तर मिला अपने आप को गैरजिम्मेदार होना. याचिकाकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता कि कब

ऑडिट अपनी क्वेरीज़ बंद कर देगा।जब लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं और नियोक्ता की राय में, कर्मचारी संतोषजनक उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे या तो जांच गठित करने की अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहिए या विचाराधीन तरीके से एक न्यायिक तंत्र के लिए दबाव डालना चाहिए। दायित्व को अंतिम रूप देने के लिए किसी मुकदमे की संस्था के नियम या सामान्य कानून उपाय का सहारा लेना। यदि दायित्व को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा नियोक्ता दायित्व को अपनी मर्जी से सुनिश्चित कर सके।

(6) विश्वविद्यालय ने आर-1 के तहत असमायोजित अग्रिमों की एक सूची दी है। मैं केवल उन अनेक प्रविष्टियों के संदर्भ से प्रभावित नहीं हूँ जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राशि की प्राप्ति स्वयं से इनकार नहीं की

जाती है। यह याचिकाकर्ता के दावों का विवरण है कि उन्हें खर्च कर दिया गया है जिसे विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया है। वे निश्चित रूप से केवल कर्मचारी को संचार के लंबे दौर में शामिल करके हल नहीं किए जा सकते थे। संचार बंद हो गया होगा और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई होगी।

(7) इस बारे में कई न्यायिक दृष्टिकोण रहे हैं कि यह कितना गंभीर है मुद्दा तब है जब सेवानिवृत्ति लाभों का वितरण करना नियोक्ता के कर्तव्य की बात आती है। यह सच है कि उनकी सेवा के दौरान किसी भी दायित्व के लिए भविष्य निधि संचय के विरुद्ध समायोजन तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ऐसे समायोजन की अनुमति देने वाले विशिष्ट प्रावधान न हों। इस मामले में, विनियम 6 ऐसे समायोजनों को विधिवत संभव बनाता है। मुझे ऐसे कई निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं दिखती, जिनका याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हवाला दिया है, जहां भविष्य निधि बकाया के विरुद्ध दायित्व का समायोजन रद्द कर दिया गया है, जहां ऐसे समायोजन के लिए कोई नियम या नियम नहीं थे। ऐसे निर्णय भी हैं जो मानते हैं कि भविष्य निधि के लिए देय राशि का कोई भी हिस्सा कुर्की का विषय नहीं हो सकता है। हम ऐसी स्थितियों से नहीं निपट रहे हैं और इसलिए, मैं उन्हें लागू करने का कोई कारण नहीं ढूंढूंगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम डॉ. शीतला प्रसाद नागेंद्र और अन्य[1] (1) मामले में, एक सेवानिवृत्त शिक्षक की देनदारी के विरुद्ध पेंशन और सेवानिवृत्ति के बकाए को समायोजित करने का प्रयास, जो लगातार आधिकारिक क्वार्टर पर कब्जा कर रहा था, को अवैध पाया गया। यह तर्क देते हुए कि पेंशन और ग्रेच्युटी अब सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले किसी इनाम का मामला नहीं है, बल्कि उनके हाथों में प्राप्त मूल्यवान अधिकार और संपत्ति हैं और निपटान और संवितरण में किसी भी देरी को देखा जाना चाहिए। गंभीरता से। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा दिखाई गई सुस्ती को सही ठहराया वसूली के अपने अधिकार को लागू करने के लिए कानून के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करना प्रतिवादी से क्वार्टरों का कब्ज़ा या दायित्व तय करना या तथाकथित दंडात्मक किराया निर्धारित करना स्वयं ही उन्हें समायोजन के अधिकार से वंचित कर देगा। मैं इस मामले में भी वही तर्क लागू करूंगा, क्योंकि, एक कर्मचारी, जो अपने दायित्व से इनकार करता है, उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दायित्व निर्धारित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के अभाव में उस पर ऐसा दायित्व नहीं डाला जा सकता है। इससे भी अधिक, इस मामले में, जिस देनदारी को तय करने की मांग की गई थी, वह सेवानिवृत्ति के समय या उससे ठीक पहले प्राप्त अग्रिम के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी सेवा के दौरान 20 वर्षों की अवधि में किए गए अग्रिम के लिए थी।

(8) मुझे नियमों द्वारा स्वीकार्य किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हुए बिना भविष्य निधि से कटौती करने में नियोक्ता का रवैया अक्षम्य लगता है। देनदारी के विरुद्ध कथित समायोजन पर भविष्य निधि की बकाया राशि जारी न करना, जो निर्धारित नहीं है, अस्थिर है। याचिकाकर्ता को 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ भविष्य निधि का भुगतान तुरंत किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारों से अन्यायपूर्ण इनकार के लिए 2 लाख रुपये के हर्जाने का दावा किया है। ब्याज के पुरस्कार को ध्यान में रखते हुए, मैं मुआवजे को दावे के एक अलग शीर्षक के रूप में अस्वीकार करता हूं।

---

[1] एआईआर 2001 एससी 2443

(9) इसलिए, रिट याचिका को प्रतिवादियों को 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ भविष्य निधि जारी करने का निर्देश देने की अनुमति दी जाती है, जिसकी लागत 10,000/- रुपये आंकी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा।